

ए. एम. रमन्ना

बनाम

लैंड ट्राइब्यूनल, मांड्य तालुक और अन्य

12 जुलाई, 2007

(डॉ. अरिजीत पसायत और लोकेश्वर सिंह पंत, जे. जे.)

भूमि कानून: "- मुकदमे का गिरवीकरण -भूमि मोचन और कब्जा वापस लिया गया- गिरवीकरण को इस आधार पर अधिभोग का अधिकार दिया गया कि गिरवी के मोचन के बाद उसे भूमि पट्टे पर दी गई थी- पट्टा विलेख की सत्यता पर संदेह करते हुए और-अपीलीय प्राधिकरण के खरीदार द्वारा चुनौती दी गई, गिरवी के दावे को खारिज कर दिया-उच्च न्यायालय ने अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया-अपील पर, कहा गया: उच्च न्यायालय ने अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में गलती की-पहाड़ी दस्तावेजों में गिरवी का नाम किरायेदार के रूप में दर्ज नहीं किया गया था-पट्टा पुस्तक और पहाड़ी दस्तावेजों में दर्ज किए गए खरीदार के नाम के बजाय- इसके अलावा, गिरवी गांव के पटेल थे और उन्हें इसकी पूरी जानकारी थी और खरीदार- से भूमि कर प्राप्त करने के लिए पट्टा बुक में भी हस्ताक्षर किए थे-कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1961-धारा 12 आई. ए.

18.11.1960 को, 'बी' ने 10 साल की अवधि के लिए अपने भाई 'टी' के पक्ष में गिरवी रखा। हालांकि बंधक अवधि वर्ष 1970 तक थी, 'बी' ने 27.8.1963 पर ही बंधक को छोड़ा लिया। हालांकि, मूल किरायेदार 'टी' का मामला यह था कि 30.8.1963 पर, 'बी' ने सूट भूमि सहित कुछ भूमि के संबंध में उसके पक्ष में एक पट्टा विलेख निष्पादित किया था। 'टी' ने वाद भूमि के संबंध में अधिभोग अधिकारों का दावा करते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसे न्यायाधिकरण द्वारा अनुमति दी गई थी। वर्ष 1972 में 'के' से भूमि का खरीदार होने का दावा करने वाले अपीलार्थी ने अपीलीय प्राधिकरण से संपर्क किया। पट्टा विलेख की सत्यता पर संदेह करते हुए अपीलीय प्राधिकरण ने 'टी' के दावे को खारिज कर दिया। इसके बाद उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय का विचार था कि पट्टा विलेख की वास्तविकता के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। अंत में, यह निष्कर्ष निकाला गया कि अपीलार्थी द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष या अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष 'के' की जांच नहीं की गई थी, ताकि उसके मामले को साबित किया जा सके कि यह 'के' था जो 1963 से 1972 तक भूमि का मालिक था जिससे अपीलार्थी ने वर्ष 1972 में भूमि खरीदी थी। तदनुसार अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को दरकिनार कर दिया गया। इसीलिये वर्तमान अपील भी।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कहा:-

1. यह माना जाता है कि 'बी' द्वारा कब्जा मोचन के समय लिया गया था, और कब्जा 'के' को दिया गया था और 'के' ने अपीलार्थी को कब्जा सौंप दिया था। (पैरा 10) [312-जी]

2. अपनी प्रतिपरीक्षा में 'टी' ने स्वीकार किया था कि लगभग 2 से 3 वर्षों तक बंधक को भुनाने के बाद उसने भूमि का गुथिगे नहीं किया था और वही इस छोटे भाई 'बी' को दे दिया था। [पैरा 13] (313-जी)

3. अपीलीय प्राधिकरण ने 'टी' की प्रतिपरीक्षा में बयान का उल्लेख किया और यह अभिनिर्धारित किया कि वह 30.8.1963 पर भूमि के कब्जे में नहीं था; भूमि के पहाड़ी दस्तावेजों की जांच की गई और यह नोट किया गया कि 'टी' द्वारा भूमि का कब्जा 30.9.1963 से नहीं था और यह स्थापित नहीं किया गया था। भूमि के पहाड़ी दस्तावेजों में उनका नाम किरायेदार के रूप में दर्ज नहीं किया गया था। 30.9.1963 पर, विवादित भूमि को अपने ससुर को बेच दिया। विवादित भूमि की कंदयम पट्टा पुस्तक और पहाड़ी दस्तावेजों में इस तरह की बिक्री के बाद, खरीदार का नाम 'के' दर्ज किया गया था। उन्होंने राज्य सरकार 'टी' को भूमि कर का भुगतान भी किया था, जिसे गाँव पटेल ने खुद कंदयारन में भूमि कर प्राप्त करने के लिए हस्ताक्षरित किया था। उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, उसके विपरीत, अपीलीय प्राधिकरण ने पट्टा विलेख की वास्तविकता के बारे में प्रश्न की विस्तार से जांच की है। भूमि न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज

किए गए बयान में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि विवादित भूमि पर 'के' और उनके दामाद 'बी' द्वारा संयुक्त रूप से खेती की जा रही थी। इसलिए, अपीलीय प्राधिकरण ने अनुमान लगाया कि बिक्री विलेख लागू था। अभिलेख पर सामग्री की जांच करने के बाद, अपीलीय प्राधिकरण ने एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया कि पट्टा विलेख एक वास्तविक दस्तावेज नहीं था और यह एक विश्वसनीय दस्तावेज नहीं था। अपीलीय प्राधिकरण ने नोट किया कि 'टी' गाँव के पटेल थे और उन्हें लेन-देन की पूरी जानकारी थी। उच्च न्यायालय ने यह ठहराते हुए गलती की कि दस्तावेज की वास्तविकता के बारे में तथ्यात्मक पहलू पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। कब्जे के दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया था।[पैरा141(314-ए-ई)]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:- सिविल अपील सं. 669/2001

1990 के संख्या 2535 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलूर के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 4.9.1998 से।

अपीलार्थी की ओर से जी. वी. चंद्र शेखर, अंजना चंद्र शेखर और पी. पी.सिंह।

प्रतिवादी के लिए गुंटूर प्रभाकर।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत जे. द्वारा दिया गया था। 1. इस अपील में कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1961 (संक्षेप में

'अधिनियम') की धारा 121-ए के तहत दायर पुनरीक्षण याचिका को अनुमति देने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है। गैर-सरकारी प्रतिवादी नंबर 2 सी. एल. थम्मैया (चूंकि मृत और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा प्रतिस्थापित) ने उच्च न्यायालय के समक्ष भूमि सुधार अपीलीय प्राधिकरण, मांड्या द्वारा पारित आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए पुनरीक्षण दायर किया था, जिसमें भूमि न्यायाधिकरण, मांड्या द्वारा पारित आदेश को उलट दिया गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष यह स्थिति थी कि अधिभोग के अनुदान के दावे को, हालांकि शुरू में भूमि न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, अपीलीय प्राधिकरण द्वारा साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर गलती से खारिज कर दिया गया था।

2. उच्च न्यायालय द्वारा संक्षेप में देखे गए पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैं: थम्मैया के दो भाई थे। लिंगेगौड़ा और बोरगौड़ा। बोरगौड़ा अब नहीं रहे और उनकी पत्नी और बेटी, केम्पम्मा और सुनंदम्मा इस अपील में क्रमशः 3 और 4 प्रतिवादी हैं। मान लीजिए, 1960 से पहले 3 भाइयों के बीच विभाजन हुआ था। थम्मैया, लिंगेगौड़ा और बोर गौड़ा। चिक्काबल्ली, मांड्या तालुक और अन्य भूमि का भूमि सर्वेक्षण No.86/1 बोरगौड़ा के हिस्से में आ गया। यह विवादित नहीं है कि 18.11.1960 पर बोरगौड़ा ने 10 साल की अवधि के लिए थम्मैया के पक्ष में विचाराधीन भूमि को गिरवी रखा। हालांकि बंधक अवधि 1970 तक थी, लेकिन उक्त बोरगौड़ा ने

27.8.1963 पर बंधक को छोड़ा लिया। यह मूल किरायेदार थम्मैया का मामला है कि बोरेगौड़ा ने विचाराधीन भूमि और तब से मूल किरायेदार सहित भूमि की 14 वस्तुओं के संबंध में अपने पक्ष में एक पट्टा विलेख निष्पादित किया और उनकी मृत्यु के बाद उनके कानूनी उत्तराधिकारी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं और किरायेदारों के रूप में भूमि का उपभोग ले रहे हैं। अपीलार्थी रमन्ना ने वर्ष 1972 में करीगौड़ा से भूमि का खरीदार होने का दावा किया था। उनके अनुसार, 30.9.1963 पर विचाराधीन भूमि को बोर गौड़ा ने अपने ससुर, करिगौड़ा के पक्ष में बेच दिया था, और लगभग 9 वर्षों के बाद करिगौड़ा ने भूमि को अपीलार्थी को बेच दिया और कब्जा भी सौंप दिया। यह भी निर्विवाद है कि, अपीलार्थी के पक्ष में बिक्री लेनदेन के बाद, मूल किरायेदार थम्मैया के रूप में, अपीलार्थी ने इस आधार पर विचाराधीन भूमि पर खेती करने का विरोध किया कि वह किरायेदार है। अपीलार्थी रमन्ना ने 1972 के ओ. एस. संख्या 26 में एक मुकदमा दायर किया और मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन किया गया और दीवानी न्यायालयों को किरायेदारी के प्रश्न पर निर्णय लेने से रोक दिया गया था, उक्त मुकदमे को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। जैसा कि पहले कहा गया है, 1974 के कर्नाटक अधिनियम संख्या 1 द्वारा संशोधित अधिनियम के लागू होने के बाद, मूल किरायेदार, तम्मैया ने फॉर्म संख्या 7 में आवेदन दायर किया जिसमें भूमि की सभी 14 वस्तुओं के संबंध में अधिभोग अधिकारों का दावा किया गया

था। भूमि न्यायाधिकरण के बयानों को दर्ज करने से पहले और "समझौते के विलेख और किराए की प्राप्तियों पर भरोसा करते हुए न्यायाधिकरण ने मूल किरायेदार थम्मैया के पक्ष में अधिभोग अधिकार देने के लिए 2.8.1975 का आदेश जारी किया। उक्त आदेश को अपीलार्थी द्वारा एक रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और उच्च न्यायालय ने जाँ के अनुसार नए सिरे से निपटारे के लिए मामले को भूमि न्यायाधिकरण को भेज दिया। रिमांड के बाद, एक बार फिर पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया और इस तरह के नए साक्ष्य दर्ज करने के बाद, न्यायाधिकरण ने फिर से उक्त थम्मैया को अधिकार दिए। उसी से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने अपीलीय प्राधिकरण से संपर्क किया। इससे पहले कि अपीलीय प्राधिकरण को पक्षों को अतिरिक्त साक्ष्य देने का अवसर दिया गया था और इस तरह के साक्ष्य दर्ज करने के बाद, अपीलीय प्राधिकरण ने पट्टा विलेख की व्यापकता पर संदेह करते हुए पुनरीक्षण याचिकाकर्ताओं के दावे को खारिज कर दिया। इसलिए उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी।

3. उच्च न्यायालय के समक्ष यह स्थिति थी कि अपीलीय प्राधिकरण को यह अभिनिर्धारित करना चाहिए था कि थम्मैया धारा 4 के संदर्भ में एक अभिनिर्धारित किरायेदार था। यह केवल इसलिए भी प्रस्तुत किया गया था क्योंकि कथित पट्टा विलेख एक पंजीकृत दस्तावेज नहीं था जैसा कि कानून के तहत आवश्यक है, इसे एक मनगढ़ंत दस्तावेज नहीं माना जा

सकता है। उक्त समझौते के आधार पर बोरगौड़ा की 14 भूमि किरायेदार थम्मैया को पट्टे पर दी गई थी और उस विवादित भूमि को छोड़कर शेष 13 भूमि जो निपटान विलेख के तहत पत्नी और बेटी को दी गई थी, केवल उक्त समझौते के आधार पर मूल किरायेदार को दी गई थी। 4. उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थियों का रुख यह था कि अपीलीय प्राधिकरण प्रत्येक मुद्दे को विस्तृत और विस्तार से निपटाता है और अधिनियम की धारा 121 के तहत अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा प्राप्त तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह इंगित किया गया था कि मालिकाना हक में पूर्ववर्ती करिगौड़ा उस भूमि के कब्जे में थे जो विचाराधीन थी क्योंकि 13.9.1960 जैसा कि अपीलीय प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया था। इसलिए बोरगौड़ा द्वारा और 1972 के बाद कोई पट्टा नहीं बनाया जा सकता था क्योंकि करिगौड़ा द्वारा बिक्री की गई थी और क्योंकि उनके और पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के बीच या 1963 से करिगौड़ा और पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के बीच मकान मालिक और किरायेदार का कोई संबंध नहीं था। पुनरीक्षण याचिकाकर्ता अधिभोग अधिकार प्रदान करने का हकदार नहीं था।

5. उच्च न्यायालय का विचार था कि पट्टा विलेख की वास्तविकता के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। अंत में, यह निष्कर्ष निकाला गया कि रामन्ना द्वारा न्यायाधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष करिगौड़ा से

पूछताछ नहीं की गई थी, ताकि उनके मामले को साबित किया जा सके कि यह करिगौड़ा ही थे जो 1963 से 1972 तक भूमि के मालिक थे, जिनसे रामन्ना ने वर्ष 1972 में भूमि खरीदी थी। तदनुसार अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को दरकिनार कर दिया गया।

6. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का आदेश तथ्यों और कानून के आधार पर समर्थनीय नहीं है। उच्च न्यायालय ने गलती से कहा है कि पट्टा विलेख की वास्तविकता के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। स्वीकार किया गया तथ्य यह है कि मोचन के समय कब्जा ले लिया गया था। कब्जा करीगौड़ा को दिया गया था और करीगौड़ा ने इसे अपीलार्थी को दे दिया था। दावे का आधार पट्टा-विलेख और किराया रसीदें थीं। राजस्व अभिलेखों में थम्मैया का नाम नहीं था।

7. दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया।

8. कुछ महत्वपूर्ण तिथियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्ष 1960 में एक विभाजन हुआ और विवादित संपत्ति सर्वेक्षण No.86/1 का स्वामित्व कुछ अन्य भूखंडों के साथ बोरगौड़ा के पास आया। 18.11.1960 को बोरगौड़ा ने अपने भाई थम्मैया के साथ संपत्ति को दस साल की अवधि के लिए गिरवी रखा।

9. उक्त संपत्ति को 27.8.1963 पर भुनाया गया था। 30.9.1963 पर बोरेगौड़ा ने संपत्ति अपने ससुर करिगौड़ा को बेच दी।

10. जैसा कि स्वीकृत स्थिति के ऊपर उल्लेख किया गया है कि मोचन के समय कब्जा ले लिया गया था, और कब्जा करीगौड़ा को दे दिया गया था, और करीगौड़ा ने अपीलार्थी को कब्जा सौंप दिया था।

11. 01.03.1974 में यह अधिनियम लागू किया गया था। यह विशेष रूप से प्रदान किया गया था कि भूमि सरकार में निहित हो और किरायेदारों को अधिभोग अधिकार का दावा करने का अधिकार दिया गया था। थम्मैया ने भूमि न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका दायर की और करिगौड़ा के अधीन किरायेदार होने का दावा किया। दिलचस्प बात यह है कि बोरेगौड़ा को बिक्री के बाद नहीं देखा गया था। किरायेदारी के दावे को शुरू में स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन उच्च न्यायालय ने आदेश को दरकिनार कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेज दिया। भूमि न्यायाधिकरण ने पुनः अधिभोग किरायेदार के दावे को मंजूरी दे दी।

12. अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष निर्धारण के लिए निम्नलिखित बिंदु तैयार किए गए थे:

(क) क्या विवादित भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है?

(ख) क्या विवादित भूमि को 01.03.1974 को किराए पर लिया गया

था या उससे तुरंत पहले?

(ग) 01.03.1974 पर या उससे तुरंत पहले, क्या पहला प्रतिवादी बोरेगौड़ा के तहत कानूनी रूप से विवादित भूमि पर खेती करने वाला किरायेदार था?

(घ) क्या भूमि न्यायाधिकरण का आदेश वैध है?

(ङ) इस अपील में कौन सा उचित और उपयुक्त आदेश पारित किया जा सकता है? जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दावे का आधार पट्टा-विलेख और किराए की रसीदें थीं। अपीलीय प्राधिकरण ने नोट किया कि इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि विवादित भूमि पर थम्मैया का कब्जा था। अपीलार्थी ने 21.7.1972 पर बिक्री-विलेख के तहत भूमि खरीदी थी। यह साबित करने के लिए कि वह कानूनी रूप से भूमि पर खेती कर रहा था, थम्मैया ने 30.8.1963 दिनांकित समझौते और 02.03.1964, 28.02.1966, 18.01.1965, 06.03.1970, 02.03.1969 और 16.02.1968 दिनांकित रसीदों पर भरोसा किया। अपीलीय प्राधिकारी ने नोट किया कि थम्मैया ने उस भूमि में किरायेदारी के अधिकार हासिल करने का प्रयास किया जो उनके छोटे भाई के हिस्से में चली गई है। इसलिए, उन्हें यह पता था कि बोरेगौड़ा ने भूमि न्यायाधिकरण के समक्ष अपने बयान में कुछ महत्वपूर्ण बयान देते हुए विवादित भूमि को अपने ससुर करिगौड़ा को एक बिक्री विलेख के तहत बेच दिया था। अपीलीय प्राधिकरण ने नोट किया कि परिवार में विभाजन के बाद बोरेगौड़ा ने

थम्मैया से ऋण प्राप्त करके 10 साल की अवधि के लिए अपने हिस्से में आई भूमि के कब्जे के साथ गिरवी रखा था। दस साल की अवधि पूरी होने से पहले बोरैगौड़ा ने 27.8.1963 पर गिरवी रखी गई राशि का भुगतान किया और कब्जा वापस प्राप्त कर लिया। बोरैगौड़ा ने 27.8.1963 पर थम्मैया के बंधक ऋण का भुगतान किया। अपनी प्रतिपरीक्षा में थम्मैया ने स्वीकार किया था कि लगभग 2 से 3 वर्षों तक बंधक को भुनाने के बाद उसने जमीन का उपभोग नहीं किया था और अपने छोटे भाई को तीन साल की अवधि के लिए रियायत पर दिया था। गाँव छोड़ने के बाद उन्होंने फिर से ज़मीन का उपभोग जारी रखा और वह खुद ऐसा कर रहे थे।

14. अपीलीय प्राधिकरण ने प्रतिपरीक्षा में बयान का उल्लेख किया और यह निर्णय लिया कि 30.8.1963 पर भूमि पर उनका कब्जा नहीं था। भूमि के पहाड़ी दस्तावेजों की जांच की गई और यह नोट किया गया कि थम्मैया द्वारा भूमि का कब्जा और उपभोग 30.9.1963 से नहीं था और यह स्थापित नहीं किया गया था। भूमि के पहाड़ी दस्तावेजों में उनका नाम किरायेदार के रूप में दर्ज नहीं किया गया था। 30.9.1963 पर बोरैगौड़ा ने विवादित जमीन अपने ससुर को बेच दी। कंदयम पट्टा पुस्तक और पहाड़ी दस्तावेजों में करैगौड़ा के विवादित भूमि नाम की इस तरह की बिक्री के बाद खरीदार को दर्ज किया गया था। उन्होंने राज्य सरकार को भूमि कर का भुगतान भी किया था। थम्मैया, जो गाँव के पटेल थे, ने खुद कंदयम पट्टा पुस्तक में भूमि कर प्राप्त करके पुट्टा पुस्तक में टिप्पणी लिखी है।

उन्होंने कंदयम में भूमि कर प्राप्त करने के लिए हस्ताक्षर किए थे। उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, उसके विपरीत, अपीलीय प्राधिकरण ने पट्टा विलेख की वास्तविकता के बारे में प्रश्न की विस्तार से जांच की है। भूमि न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए बयान में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि विवादित भूमि पर कोरेगौड़ा और उनके दामाद बोरगौड़ा द्वारा संयुक्त रूप से खेती की जा रही थी। इसलिए, अपीलीय प्राधिकरण ने अनुमान लगाया कि बिक्री विलेख लागू था। अभिलेख पर सामग्री की जांच करने के बाद, अपीलीय प्राधिकरण ने एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया कि पट्टा विलेख एक वास्तविक दस्तावेज नहीं था और यह एक विश्वसनीय दस्तावेज नहीं था। अपीलीय प्राधिकरण ने नोट किया कि थम्मैया गाँव के पटेल थे और उन्हें लेन-देन की पूरी जानकारी थी। उच्च न्यायालय ने यह ठहराते हुए गलती की कि दस्तावेज की वास्तविकता के बारे में तथ्यात्मक पहलू पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। कब्जे के दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया था। यह भी नहीं दिखाया गया कि कोरीगौड़ा से कब कब्जा लिया गया था।

15. उपरोक्त स्थिति होने के कारण उच्च न्यायालय को अधिनियम की धारा 121-ए के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना

चाहिए था। उच्च न्यायालय का आदेश टिकाऊ नहीं है और इसे दरकिनार कर दिया गया है।

16. अपील सफल होती है लेकिन परिस्थितियों बारे में लागत के किसी भी आदेश के बिना।

अपील की अनुमति गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।